

**संपदा शुल्क संदर्भ
न्यायमूर्ति डी.के. महाजन और प्रेम चंद जैन के समक्ष
संपदा शुल्क नियंत्रक, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, पटियाला,-आवेदक।**

बनाम

**एम. एल. मनचंदा, फ़रीदाबाद टाउनशिप।-प्रतिवादी।
1970 का संपदा शुल्क संदर्भ संख्या १।**

24 जनवरी 1972.

संपदा शुल्क अधिनियम (1953 का XXXIX) - धारा 5 और 6 - पति के स्वामित्व वाली संपत्ति जो उसकी पत्नी के नाम पर बेनामी है। - क्या पत्नी की मृत्यु पर संपत्ति शुल्क लगाया जा सकता है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एक बेनामीदार संपत्ति का मालिक है और उसका स्वामित्व केवल वास्तविक मालिक के अधिभावी शीर्षक के अधीन है। वह तीसरे व्यक्ति को स्वामित्व दे सकता है और यदि उस व्यक्ति को अपने शीर्षक की बेनामी प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वह वास्तविक मालिक के विरुद्ध भी एक अच्छा शीर्षक प्राप्त कर लेता है। संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 6 के अनुसार, मृत व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय जिस संपत्ति का निपटान करने में सक्षम है, उसे उसकी मृत्यु पर हस्तांतरित माना जाता है। जहां कोई संपत्ति जिसका पति असली मालिक है, वह बेनामीदार के रूप में पत्नी के नाम पर है, तो उसे अपनी मृत्यु से पहले किसी भी समय इसे हस्तांतरित करने से कोई नहीं रोक सकता है। असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ कानूनी अधिकार उसके पास निहित है और इस प्रकार उसे उस संपत्ति के निपटान का अधिकार है। इसलिए ऐसी संपत्ति को उसकी मृत्यु के बाद हस्तांतरित माना जाएगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 5 के तहत संपत्ति शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(पैरा 9 और 12)

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (दिल्ली बैंच) द्वारा संपत्ति शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 64(1) के तहत संदर्भ, - उनके आदेश दिनांक 24 जनवरी, 1969 द्वारा 1967 के आर.ए.नंबर 1535 में इस माननीय न्यायालय की राय के लिए -68 ई.डी.ए.सं. कानून के निप्रलिखित प्रश्न पर 1966-67 का 32: क्या मामले के तथों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन से संबंधित संपत्ति के मूल्य को यह कहकर कानूनन सही ठहराया था कि मृतक उसका निपटान करने में सक्षम नहीं था और यह उसकी मृत्यु पर नहीं चला?

आवेदक की ओर से डी.एन.अवस्थी, अधिवक्ता और बी.एस.गुप्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से डी.डी. वर्मा और वकील आर. एन. नर्स्ला।

निर्णय.

इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

न्यायमूर्ति महाजन -यह संदर्भ संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 के तहत उत्पन्न हुआ है (1953 का अधिनियम संख्या 34) (इसके बाद इसे अधिनियम के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली बैंच 'सी' ने हमारी राय के लिए कानून के निप्रलिखित प्रश्न को संदर्भित किया है: -

"क्या तथों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन से संबंधित संपत्ति के मूल्य को यह कहते हुए बाहर करने का फैसला किया कि मृतक इसका निपटान करने में सक्षम नहीं था और यह उसकी मौत पर आगे नहीं बढ़ा?"

(2) जहां तक तथों का सवाल है, कोई विवाद नहीं है, हालांकि जवाबदेह व्यक्ति के विद्वान वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की कि तथों के संबंध में कुछ विवाद था। विवाद सावित्री देवी की संपत्ति से जुड़ा है। 17 नवंबर, 1963 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु की तारीख पर, उनके नाम पर दो

संपत्तियां थीं। संपदा शुल्क के सहायक नियंत्रक द्वारा इन संपत्तियों का मूल्यांकन 1,63,200/- रुपये किया गया।

(3) जवाबदेह व्यक्ति मृतिका के पति श्री एम.एल.मनचंदा हैं। संपत्ति फ़रीदाबाद में स्थित है। प्रारंभ में, इसमें 800 वर्ग गज के प्लॉट संख्या 5-सी/एल और 5-सी/2 शामिल थे। ये भूखंड विकास बोर्ड की मंजूरी के अधीन पति को आवंटित किए गए थे। आवंटन को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। बाद में, जवाबदेह व्यक्ति ने फ़रीदाबाद विकास बोर्ड से उक्त भूखंडों को उसकी पत्नी के नाम हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। यह अनुरोध इस शर्त पर स्वीकार किया गया कि पहले रु. 1408/3/- की राशि जमा की जानी चाहिए। यह राशि जमा कर दी गई और जवाबदेह व्यक्ति ने अपने पत्र, दिनांक 30 अप्रैल, 1956 द्वारा अनुरोध किया कि उक्त भूखंडों को उसकी पत्नी के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाए। बाद में, सहायक निपटान अधिकारी ने महिला को पत्र लिखा कि क्या वह चाहती है कि लीजहोल्ड अधिकारों को प्रिहोल्ड अधिकारों में परिवर्तित किया जाए। इस संचार को स्वीकार कर लिया गया और मांगी गई राशि का भुगतान जवाबदेह व्यक्ति द्वारा किया गया, जिसने बाद में अपने पैसे से एक घर का निर्माण किया, जिसका केवल भूतल का हिस्सा शुरू में बनाया गया था। इस इमारत को जवाबदेह व्यक्ति द्वारा प्रति माह 600/- रुपये के किराए पर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉर्मर्स लिमिटेड को दे दिया गया था और इस प्रकार वसूल की गई राशि से, यह कहा गया है कि जवाबदेह व्यक्ति ने ऊपरी मंजिल का भी निर्माण किया। आकलन वर्ष 1961-62 और उसके बाद के लिए किराये की आय पर भी जवाबदेह व्यक्ति के हाथों कर लगाया गया था। जवाबदेह-व्यक्ति द्वारा दिनांकित एक घोषणा भी है 1 नवंबर, 1963 को इस आशय का आदेश दिया गया कि वह भूखंडों के साथ-साथ घर का भी मालिक है, हालांकि वे उसकी पत्नी के नाम पर थे। इस घोषणा पत्र पर पत्नी और बेटे के भी हस्ताक्षर हैं। इस घोषणा के आधार पर बैंक द्वारा कुछ धनराशि अग्रिम दी गई।

(4) पत्नी की मृत्यु पर, जैसा कि पहले ही कहा गया है, वह संपत्ति जो उसके नाम पर थी और जिसका स्वामी पति था, अधिनियम की धारा 5 के अनुसार संपत्ति शुल्क लगाने के उद्देश्य से मृतक की संपत्ति में शामिल करने की मांग की गई थी। पति की यह दलील कि वह संपत्ति का असली मालिक

है और पत्नी केवल बेनामीदार है और इसलिए संपत्ति पत्नी की नहीं मानी जा सकती, अधिनियम की धारा 6 के आधार पर खारिज कर दी गई जो निप्रलिखित शर्तों में है:-

”जिस संपत्ति का निपटान मृतक अपनी मृत्यु के समय कर सकता था, उसे उसकी मृत्यु के बाद हस्तांतरित माना जाएगा।”

(5) जवाबदेह व्यक्ति द्वारा संपदा शुल्क के जोनल अपीलीय नियंत्रक के समक्ष की गई अपील पर कोई सफलता नहीं मिली। अधिनियम की धारा 63 के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में एक और अपील दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल ने अपील की अनुमति दी और माना कि मामला अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत नहीं आता है। अधिनियम की धारा 64(1) के तहत इस न्यायालय में मामले के विवरण के लिए ट्रिब्यूनल में एक आवेदन किया गया था। यह आवेदन स्वीकार कर लिया गया और पहले से संदर्भित कानून के प्रश्न को संदर्भित किया गया है।

(6) विभाग के विद्वान वकील 1 का तर्क 1 कि ट्रिब्यूनल यह मानने में गलत हो गया है कि विवाद में संपत्ति को अधिनियम की धारा 6 के तहत मृतक की संपत्ति नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि संपत्ति का असली मालिक मृतक नहीं था। मृतक का पति ही मालिक था। विभाग के विद्वान वकील ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को चुनौती नहीं देते हैं, अर्थात्:

”यह सबूत, हमारी राय में, पूरी तरह से साबित करता है कि जवाबदेह व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बेनामी नाम पर अपने पैसे से दो भूखंड खरीदे और उसके बाद उसने अपने पैसे से उस पर एक इमारत का निर्माण किया। इसलिए, हम मानते हैं कि जवाबदेह व्यक्ति ही इस संपत्ति का असली मालिक है।”

इस निष्कर्ष से जो बात सामने आती है वह यह है कि पत्नी बेनामीदार है क्योंकि संपत्ति उसके नाम पर अर्जित की गई थी और पति ही असली मालिक है, संपत्ति प्राप्त करने के साथ-साथ भूखंड पर भवन निर्माण के लिए सारा पैसा उसकी जेब से प्राप्त हुआ है। हालाँकि, प्रश्न का निपटारा धारा 6 की भाषा पर किया जाना है।

(7) इस स्तर पर जवाबदेह व्यक्ति के विद्वान वकील के इस तर्क का उल्लेख करना उचित होगा कि पत्नी बिल्कुल भी बेनामीदार नहीं थी और किसी भी समय पत्नी को दी गई संपत्ति में कोई शीर्षक

नहीं था। मजे की बात यह है कि यह कोई ऐसा मामला नहीं था जो कभी सहायक नियंत्रक या क्षेत्रीय अपीलीय नियंत्रक या न्यायाधिकरण के समक्ष स्थापित किया गया हो। मामला इस संक्षिप्त आधार पर आगे बढ़ा कि संपत्ति पत्नी के नाम पर अर्जित की गई थी, लेकिन उस पर विचार पति की ओर से किया गया था और इस प्रकार पति संपत्ति का असली मालिक था, और पत्नी केवल एक बेनामी थी। हम भी इसी संक्षिप्त आधार पर आगे बढ़ते हैं।

(8) कम से कम कहने के लिए, मामला रेस इंटीग्रा का नहीं है। इस मुद्दे पर तीन प्रत्यक्ष निर्णय हैं लेकिन ट्रिब्यूनल के समक्ष केवल एक का हवाला दिया गया था। ट्रिब्यूनल के समक्ष जिसका हवाला दिया गया वह है श्रीमती शांताभाई जाधव बनाम संपदा शुल्क नियंत्रक¹। अन्य दो हैं, श्रीमती डेंडबाई बोमन शाह बनाम संपदा शुल्क नियंत्रक, ए.पी.² और आलोक मित्र बनाम नियंत्रक संपदा शुल्क³। इन सभी मामलों में, संपत्ति बेनामी अर्जित की गई थी और फिर भी बेनामीदार के हाथों में होने पर उसे मृत्यु पर उसकी संपत्ति माना जाता था। यह विशेष रूप से अधिनियम की धारा 6 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। श्री मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त⁴ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें उनके आधिपत्य ने एक बेनामी लेनदेन की तुलना एक दिखावटी लेनदेन से करते हुए निम्रानुसार देखा:-

“लेन-देन के इन दो वर्गों के बीच मूलभूत अंतर यह है कि जबकि पूर्व में एक ऑपरेटिव ट्रांसफर होता है जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसफरी में स्वामित्व निहित होता है। उत्तरार्द्ध में ऐसा कुछ भी नहीं है, हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के बावजूद हस्तांतरणकर्ता का स्वामित्व बरकरार रहेगा।”

(9) यह इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है कि एक बेनामीदार सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए संपत्ति का मालिक है और उसका स्वामित्व केवल वास्तविक मालिक के अधिभावी शीर्षक के अधीन है। वह किसी तीसरे व्यक्ति को स्वामित्व दे सकता है और यदि उस तीसरे व्यक्ति को उसके शीर्षक की बेनामी प्रकृति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वह वास्तविक मालिक के विरुद्ध भी

¹ 51 आई.टी.आर. एस्टेट डिटी सप्प.

² 66 आई.टी.आर. 385.

³ 82 आई.टी.आर. 430

⁴ ए.आई.आर.1957 एस.सी., 49.

एक अच्छा शीर्षक प्राप्त कर लेता है। इसलिए, उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, ट्रिब्यूनल के तर्क की वैधता की जांच करनी होगी।

(10) ट्रिब्यूनल ने विभाग के विरुद्ध निर्णय लेते हुए और सहायक नियंत्रक के साथ-साथ जोनल अपीलीय नियंत्रक के निर्णय को पलटते हुए निम्नानुसार कहा:-

“अब हमारे विचार के लिए यह सवाल उठता है कि क्या इस संपत्ति का मूल्य मृतक की संपत्ति में सिर्फ इसलिए शामिल किया जा सकता है क्योंकि दो खाली भूखंडों का आवंटन उसकी पत्ती के नाम पर किया गया था। हमारे अंतिम निर्णय के लिए प्रश्न यह है कि क्या मृतक के पास अपने जीवनकाल के दौरान इस संपत्ति का निपटान करने की शक्ति है, केवल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि संपत्ति उसके नाम पर थी। जवाबदेह व्यक्ति के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह तर्क देना असंभव है कि मृतक के पास संपत्ति का निपटान करने की शक्ति केवल इसलिए थी क्योंकि संपत्ति उसके नाम पर आवंटित की गई थी या थी। उन्होंने कानून की उस चिर-प्रसिद्ध उक्ति का उल्लेख किया कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता, जो उसके पास नहीं है। जब मृतक के पास इस संपत्ति पर कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं था, तो उसने तर्क दिया कि वह उक्त संपत्ति का निपटान कैसे कर सकती थी और भले ही उसने इसके संबंध में बिक्री विलेख या कोई अन्य विलेख निष्पादित किया हो, फिर भी वह उसके तहत एक वैध शीर्षक कैसे स्थानांतरित कर सकती थी। उन्होंने बताया कि किसी संपत्ति के मालिक की संपत्ति हस्तांतरित करने की शक्ति उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति या उसके नाम पर मौजूद संपत्ति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि संपत्ति के उसके स्वामित्व पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, कानून का कोई प्रावधान या सिद्धांत नहीं है जो संपत्ति के वास्तविक मालिक को संपत्ति के निपटान से अयोग्य ठहराता है क्योंकि यह उसके नाम पर नहीं है या इसे उसके नाम पर अर्जित नहीं किया गया है। इसी तरह उन्होंने तर्क दिया कि कानून का कोई प्रावधान या सिद्धांत नहीं है जो एक बेनामीदार को किसी संपत्ति के संदर्भ में एक वैध शीर्षक पारित करने के लिए अधिकृत करता है, सिर्फ इसलिए कि संपत्ति उसके नाम पर खरीदी गई है या संपत्ति उसके नाम पर है। हम राजस्व के इस तर्क से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हैं कि मृतक के पास संपत्ति का निपटान करने की शक्ति थी क्योंकि आवंटन उसके पक्ष में किए गए थे या सरकारी रिकॉर्ड में संपत्ति उसके नाम पर थी। चूँकि उसके

पास संपत्ति का कोई स्वामित्व नहीं था, इसलिए वह क्रेता को कोई स्वामित्व नहीं दे सकती थी। आगर उसने कोई विक्रय पत्र निष्पादित भी किया होता तो भी उसे संपत्ति का असली मालिक नहीं मिल पाता। इन परिस्थितियों में यह मानना असंभव है कि उसके पास अपने जीवनकाल के दौरान इस संपत्ति का निपटान करने की शक्ति थी।

(11) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यदि ऊपर दिए गए कानूनी प्रस्ताव और जो सुप्रीम कोर्ट की राय से समर्थित हैं, को ध्यान में रखा जाता है, तो ट्रिब्यूनल के तर्क की मिथ्याता स्पष्ट हो जाएगी।

(12) यह हमें धारा 6 की भाषा की जांच करने के लिए लाता है। यह धारा केवल इतना कहती है कि जिस संपत्ति का निपटान मृतक अपनी मृत्यु के समय करने में सक्षम था, उसे उसकी मृत्यु पर हस्तांतरित माना जाएगा। इस तथ्य के बावजूद कि पति ही संपत्ति का असली मालिक था, उसकी मृत्यु से एक मिनट पहले पत्नी को संपत्ति हस्तांतरित करने से कोई नहीं रोक सकता था। असली मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ कानूनी हक उसके पास निहित है और इस प्रकार उसे उस अधिकार का निपटान करने का अधिकार है, और एक बार उस अधिकार को स्वीकार कर लेने के बाद, संपत्ति को उसकी मृत्यु के बाद हस्तांतरित माना जाएगा और इसलिए, अधिनियम की धारा 5 के तहत संपत्ति शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी है। इस निष्कर्ष से बचना संभव नहीं है।

(13) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में देते हैं, अर्थात् विभाग के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध। हालाँकि, हम लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देने का प्रस्ताव करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1974)2

अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए
उपयुक्त रहेगा।

स्मृति

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कुरुक्षेत्र, हरियाणा